

नौनिहालों की थाली में ‘शाकाहारवाद की राजनीति’ जायज नहीं

विद्या भूषण रावत

भारत के सभी राज्य सरकारों को इस संदर्भ में तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों को स्कूल में न केवल पौष्टिक भोजन कराया जाए अपितु उन्हें अच्छा नाशता भी मिले ताकि वे अच्छे से पढ़ सकें। बता रहे हैं विद्या भूषण।

कर्नाटक सरकार ने राज्य के 178 इंदिरा रसोईधरों को हिंदूवादी संगठन इंटरेनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्सनेंस (इस्कॉन) के हवाले करने का फैसला किया है। इसके लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई है। कर्नाटक के अधिकारियों ने विशेष उपबंधों का उपयोग कर इस्कॉन को यह कार्य दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक यह 'जनहित' का मामला है और इस्कॉन जनहित में बहुत-से कार्य कर रहा है।

गौरतलब है कि इस्कॉन द्वारा संचालित अक्षयपात्र फाउंडेशन के जरिए अनेक राज्यों के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन मुहूर्या करवाया जा रहा है। कनाटक में तो उसे पहले से ही प्रमुखता दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों ने भी अपने स्कूलों में मध्याह्न भोजन के संचालन के लिए इस्कॉन की सेवाएं ली हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें भी उनके कार्यों और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए खाने की गुणवत्ता से बहुत खुश हैं। वैसे कोई भी दानदात् संस्था जब भोजन देने को तैयार हो तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी संगठन बिना सरकार की मदद के यह काम नहीं करती। अभी भी इंदिरा रसोई के लिए इस्कॉन ने तीन समय के खाने के लिए 78 रुपए की मांग रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि गरीब स्कूली छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना मानवीय काम है लेकिन यह भी समझना आवश्यक है कि इस्कॉन जैसी संस्था भी सरकारी अनदान ले रही है।

अब प्रश्न इस बात का नहीं है कि इस्कॉन की संस्था अक्षयपात्र हमेशा से विवादों में घिरी रही है। दरअसल यह विवाद नहीं, अपितु लोगों की खान-पान संबंधी



आदतों के साथ छेड़छाड़ करने का मसला है। अक्षयपात्र मध्याह्न भोजन में प्याज, लहसुन, अदरक रहित व्यंजन उपलब्ध कराता है। अक्षयपात्र संगठन कहता है कि वह बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रदान करता है। लेकिन अनेक लोगों की शिकायत रही है कि क्या बच्चों को शाकाहारी-मांसाहारी की बहस में फंसाना उचित है। क्या यह जरूरी नहीं कि बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाय।

कर्नाटक हिन्दुत्व के संगठनों का गढ़ बन चुका है। दिसंबर, 2021 में राज्य सरकार ने कहा कि बच्चों को मध्याह्न भोजन में अंडे भी दिए जाएं। इस पर हिंदूवादी संगठनों के अलावा लिंगायत भी गुस्से में लाल-पीले हो गए। अब अक्षयपात्र फाउंडेशन खुलकर अंडों का मुखालफत कर रहा है। यह संगठन केवल मांसाहार का विरोध नहीं करते, अपितु बच्चों के शाकाहार को भी निर्यन्त्रित कर रहा है।

सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। उनके मां-बाप काम पर होते हैं। इसलिए यदि बच्चों को अच्छा मध्याह्न भोजन मिलता है तो उनका शारीरिक विकास भी होगा। मध्याह्न भोजन योजना का मक्सद भी यही रहा है। दरअसल, कर्नाटक में आधिकारिक तौर पर कई जिलों में बच्चों के कुपोषण की खबरें थीं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही राज्य के शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर के भोजन में अड़े खिलावें की बात कही। लेकिन हिंदूवादी संगठनें इसके विरोध में आ गईं। कुछ का कहना है कि यह बच्चों में तामसिक संस्कार डालेगा। अब इस प्रकार के बैंटुके विरोध का क्या करें। क्या हमारे बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलना चाहिए?

हाल ही में इस विषय पर कार्य कर रही डाक्टर मनीषा बांगर ने एक पते की बात कही। वह कहती हैं कि बच्चों को पौष्टिक भोजन देना जरूरी है। उन्होंने हिन्दू संगठनों के पाखंड पर सावल उठाया और कहा कि यदि आप बच्चों को अंडे देने से इतना

A group of school children, mostly boys, are sitting at a long table in a classroom or cafeteria, eating their lunch. They are wearing blue uniforms. The children are focused on their meal, which consists of flatbread and yellow rice. The setting appears to be a simple, functional space.

खिलाने की बात करते ? पनीर और दूध तो बेहद पौष्टिक हैं और बच्चों को वह खाने में अच्छा भी लगेगा ।

मध्याह्न भोजन में पौष्टिकता महत्वपूर्ण दूसरी ओर तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इस मामले में एक अभिनव प्रयोग किया है। वहां बच्चों को दोपहर के भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। बताते चलें कि तमिलनाडु भारत का वह पहला राज्य है, जिसने बच्चों पूर्व मध्याह्न भोजन योजना को अपने राज्य में चलाया और बच्चों को पौष्टिक खाना दिया। सरकार एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहती है कि यदि बच्चों को पढ़ने से पहले अच्छा नाश्ता मिल जाए तो वे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अनेक बच्चे स्कूल समय पर पहुंचने के लिए घर से कछु भी खाकर नहीं चलते हैं और उनके लिए दोपहर तक बिना खाए पिए पढ़ना मुश्किल होता है। साथ ही, इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार ने इस दिशा में सोचा और बच्चों को पौष्टिक नाश्ता देने की घोषणा की।

यह बात भी अब सामने आ रही है कि अधिकांश राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना के प्रति सकरात्मकता नहीं है। वजह यह कि यह योजना गरीब परिवारों से आनेवाले बच्चों के लिए है, जिनमें अधिकांश दलित-बहुजन हैं। इस्कॉन जैसे हिन्दू संगठन किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं कि इन बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले। इन संगठनों के लिए लाहसुन, प्याज, अदरक और अंडे आदि समस्याएं हैं।

सवाल है कि क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि बच्चों को नाश्ते में दूध-केला या दूध-दलिया, या फिर हॉलिर्मस और इसके जैसे अन्य पूरक पौष्टिक आहार मिले? आखिर कबतक हमारे बच्चों को कमज़ोर बनाने की उनकी साजिशों कामयाब होती रहेंगी?

दरअसल इस्कॉन द्वारा संचालित अक्षयपात्र जैसे संगठनों को आगे कर सकरें बच्चों के भोजन के सांस्कृतिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं। भोजन का अधिकार मात्र पेट भरने का अधिकार नहीं है, अपितु सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत भोजन का अधिकार भी है। क्या ये संगठन यह नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चों को पौष्टिक भोजन देंगे और उसमे दूध, पनीर आदि भी शामिल हों।

सरकारी स्कूलों में
अधिकांश बच्चे गरीब
परिवारों से आते हैं। उनके
मां-बाप काम पर होते हैं।
इसलिए यदि बच्चों को
अच्छा मध्याह्न भोजन मिलता
है तो उनका शारीरिक
विकास भी होगा। मध्याह्न
भोजन योजना का मकसद
भी यही रहा है।

दक्षिण मे कोई उत्तर भारत या पूर्वी भारत का भोजन। सवाल केवल शाकाहार का ही नहीं है। अक्षयपात्र और अन्य धार्मिक संस्थानें, जिन्हें सरकारें आगे बढ़ा रही हैं वे तो बच्चों को प्याज और लहसुन भी नहीं खिलाना चाहती हैं, क्योंकि इन्हे वे तामसिक भोजन कहते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई केवल शाकाहारी और मांसाहारी होने की नहीं है, अपितु उससे भी आगे की है। अब आपको शाकाहारी भोजन भी उनलोगों की तरह करना है जो दाल में चीनी डाले या उसे पानी की तरह पिए। भारत के अलग अलग प्रांतों मे भी बहुत विविधताएँ हैं। केवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, करेल या तेलंगाना मे भी एक प्रकार का भोजन नहीं है। अलग-अलग किस्म का भोजन बनता है और यही हमारी ताकत है। निश्चित तौर पर विविधता हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है, क्योंकि हम इससे सीखते हैं और इसलिए इन्हे प्रकार के पकवानों के आधार पर ही भारत के भोजन को दुनिया में पसंद किया जाता है।

मसलन, हमारे भोजन में जो मसाले हैं, वे हमारी जीवन्तता के भी प्रतीक हैं। इसलिए यदि सभी को हम गुजराती खाना खिलाने की कोशिश करेंगे तो लोग उसे नहीं खाएँगे और वह जीवन में नीरसता लाने वाला ही होगा।

भारत के सभी राज्य सरकारों को इस संदर्भ में तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों को स्कूल में न केवल पौष्टिक भोजन कराया जाए अपितु उन्हें अच्छा नाश्ता भी मिले ताकि वे अच्छे से पढ़ सकें। उत्तर भारत में तो अभी ऐसी स्थिति आई ही नहीं है और भोजन में बहुत से अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं। फिलहाल, भोजन के जरिए बच्चों की खानपान की आदतों को न छेड़ें और उन्हें उनकी संस्कृति और चाहत के अनुसार भोजन मिले, यही प्रयास हो तां सबके लिए अच्छा रहेगा।

सनद रहे कि स्कूलों में दोपहर का गुणवत्तापूर्ण भोजन देना एक क्रांतिकारी प्रयास का हिस्सा है। लेकिन यह तभी सफल होगा जब सरकारों की नीतयत अच्छी होगी और इसमें शाकाहारवाद की राजनीति नहीं देवें।